विरोध | शहपुरा के व्यापारियों सहित क्षेत्रीयवासियों ने दी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

मगरमुहां स्थित टोल टैक्स में अवैध वसूली से बढ़ा आक्रोश

शहपुरा, भिटोनी, नवभारत। यह एक तार्किक और व्यावहारिक सत्य है कि यदि किसी मार्ग पर पक्की सड़क या पुल/आरओबी ब्रिज जैसी बुनियादी सुविधा ही उपलब्ध नहीं हैं, तो वहां किसी भी प्रकार का टोल टैक्स, प्रवेश शुल्क या नाका लगाने का कोई कानूनी या नैतिक औचित्य नहीं बनता है। यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या है या कोई अवैध नाका चल रहा है, तो आप इससे संबंधित आधिकारिक विभागों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

क्षेत्रीय वासियों का कहना है कि घर से निकलते ही जनता टोल लूट का शिकार हो रही है। आम आदमी से टोल के नाम पर वसूला जा रहा पैसा उपभोक्ता की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। जागरूक नागरिकों ने शहपुरा स्थित मगरमुहा के निकट टोल को हटाने के लिए प्राधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है तथा चेतावनी दी है कि यदि टोल रोड को नहीं हटाया गया तो वे जन आंदोलन शुरू करेंगे। लोगों का आरोप था कि टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और नियम के खिलाफ मनमाने ढंग से टोल टैक्स लिया जा रहा है. शहपुरा नगर वासियों एवं आसपास के गांव वालों ने कहा कि नियम के अनुसार छूट मिलने के बावजूद स्थानीय लोगों से गलत तरीके से टोल टैक्स लिया जा रहा है. इससे आम लोगों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

क्षेत्रवासियों से एकजुट होने की अपील

शहपुरा एवं आसपास के गांव के क्षेत्र के नगर वासियों ने एकजुट होकर टोल जब ब्रिज नहीं है सुविधा नहीं है तो किस बात का टैक्स वसूला जा रहा है को लेकर सभी ने एकजुट होकर इस मुद्दे पर संघर्ष करने क्षेत्र वासियों से अपील की है। युवा कांग्रेस शहपुरा सोनू दुबे ने कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो मगरमुहा शहपुरा टोल प्लाजा पर आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

कर्मचारियों पर लगाया अभद्रता का आरोप

शहपुरा नगर वासियों ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से टोल प्लाजा पर जनता से मनमानी वसूली के साथ उनसे नाके में पदस्थ कर्मचारी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने टोल कर्मियों के सत्यापन की मांग के साथ करते हुए कहा कि अनेकों बार मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं इसकी शिकायत शहपुरा थाने में भी दर्ज है। स्थानीय जनों का कहना है कि मगरमुंहा टोल टैक्स में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। वाहन चालकों से अनुचित टोल वसूला जा रहा है। टैक्स वसूली में मनमानी और टोलकर्मियों की गुंडागर्दी की शिकायतें भी आम हैं। ओवर ब्रिज धराशाई होने के बाद वाहनों को घूम कर 15 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ रहा है जिससे ट्रक ड्राइवर एवं वाहनों को आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि एमपीआरडीसी द्वारा बायपास ओवर ब्रिज निर्माण पर निर्माण के चलते सड़क बंद की गई है। जिससे वाहन से 15 मील अधिक दूरी तय करना पड़ रही है और साथ में ट्रैफिक की समस्या आम बात है लेकिन टोल प्लाजा पर छूट न देकर टोल प्लाजा पर पूरा टैक्स की वसूली की जा रही है। आलम यह है कि 10 किलो मीटर की टैक्स वसूली पर 50 किलो मीटर का टैक्स वसूला जा रहा है। मप्र ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने ट्रक संचालकों के साथ हो रही खुली लूट को बंद करने की मांग की।

बिजली कटौती से लोगों का जीना हुआ दुश्वार

▸ नल जल योजना प्रभावित, खेतों में नहीं हो पा रही रोपाई

सिहोरा, नवभारत। सिहोरा डिवीजन के अंतर्गत आने वाली गोसलपुर डीसी के अंतर्गत गोसलपुर, गांधीग्राम, रामपुर, हृदयनगर, धरमपुरा, खजुरी, भदम, जुझारी, कटरा रमखिरिया सहित अनेक गांवों में पिछले काफी दिनों से बेतहाशा बिजली कटौती लोगों को इस उमस भरी गर्मी में खून के आंसू रुला रही है

आपको बता दें कि बिजली कटौती के चलते जहां एक ओर ग्राम पंचायतो में संचालित नल जल योजना बुरी तरह प्रभावित है वहीं दूसरी ओर उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, सबसे ज्यादा फजीहत वृद्ध, बच्चे, मरीज इन्हें झेलनी पड़ रही है एवं स्कूलों में अध्यनरत छोटे बच्चों का बिजली कटौती के चलते बुरा हाल है वहीं दूसरी ओर बिजली पर आश्रित धंधे व अन्य औद्योगिक इकाइयां उनके कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। क्षेत्र के राजा दुबे, बलराम पटेल, अरुण सराफ, आदर्श चौहान, कमल पटेल, सचिन नेमा, नरेंद्र सिंह परिहार, संतोष सोनी ने विद्युत मंडल के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि गोसलपुर क्षेत्र में हो रही बेतहाशा बिजली कटौती को तत्काल रोका जाए

वहीं इस अघोषित कटौती से किसान भी बेहद परेशान हैं उनका कहना है कि खेतों में लगाई जाने वाली धान की रोपाई भी कटौती से बुरी तरह प्रभावित हो रही है, किसान दिनेश पटेल ने बताया की जहां एक ओर बारिश न होने के कारण जैसे तैसे किसान खेतों में स्थित अपने निजी बोरों से पानी भरकर धान रोपाई का कार्य कर रहा है वहीं दूसरी ओर 10 घंटे की जगह किसानों को महज 5 से 6 घंटे बिजली मिल पा रही है जिस कारण धान रोपाई का काम बुरी तरह बाधित है। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष शैलेश पटेल ने इस ओर विद्युत मंडल के उच्च अधिकारियों से ध्यान देने की मांग की है।

एक नजर में

सर्पदंश पर झाड़-फूंक की बजाए मरीज को पहुंचाए अस्पताल : सीएमएचओ

डिण्डौरी, नवभारत। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ जिले में सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि सांप के काटने पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, झाड़-फूंक या तंत्र-मंत्र का सहारा न लें, बल्कि पीड़ित को तत्काल निकटतम अस्पताल पहुंचाकर वैज्ञानिक उपचार उपलब्ध कराएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज पाण्डेय ने बताया कि वर्षा के दौरान खेतों, घरों के आसपास लकड़ी एवं घास-फूस के ढेर तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में सांपों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं।

सुशीला बाई चौकसे का निधन

नवभारत, जबलपुर। शिव नगर, दमोह नाका निवासी सुशीला बाई चौकसे का बुधवार की सुबह निधन हो गया।

उनकी अंतिम यात्रा शाम को 4:30 बजे उनके निवास से रानीताल मुक्तिधाम के लिए रवाना हुई। वे दिवंगत नन्हेलाल चौकसे की पत्नी और विजय कुमार चौकसे, दादा भाई चौकसे व प्रेम प्रकाश चौकसे की माँ थीं।

कटंगी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा

▸ आयोजन समिति की तैयारियां हुईं पूरी

नवभारत, कटंगी जबलपुर। इस वर्ष भी क्षेत्र की प्रसिद्ध भांडेर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित भगवान जगदीश स्वामी के प्राचीन मंदिर से आज गुरुवार को पारंपरिक एवं भव्य जगन्नाथ रथयात्रा निकाली जाएगी। इस धार्मिक महोत्सव को लेकर समस्त कटंगी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह भव्य आयोजन ब्रह्मलीन स्वामी केशवानंद महाराज एवं ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद महाराज के पावन स्मृति में तथा बालयोगी महंत स्वामी चक्रानंद गिरि महाराज के गरिमामय सान्निध्य में संपन्न होगा। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ होगी। कार्यक्रम अनुसार प्रात: 9 बजे भगवान का विशेष अभिषेक एवं मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक: विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन होगा, जिसमें सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात अपराह्न 3 बजे से जगदीश मंदिर से मंदिर बाड़ा तक भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथयात्रा का शुभारंभ होगा। आयोजक समिति सहित समस्त कटंगी नगरवासियों ने सभी धर्मप्रेमी जनता से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारी संख्या में उपस्थित होकर रथयात्रा को सफल बनाने की अपील की है।

शासकीय हाई स्कूल को सिगौंद में स्थानांतरित करने पर जताया विरोध

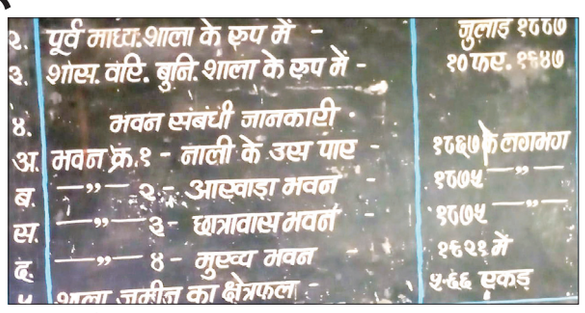

पनागर, नवभारत। पनागर नगर की धरोहर कहे जाने वाले एतिहासिक विद्यालय शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल पनागर को सिगौंद में स्थानांतरित करने पर शासन की तानाशाही पर पनागर वासियों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

वरिष्ठ कर्मचारी नेता जवाहर केवट ने बताया कि, पनागर नगर का गौरव शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल पनागर को अधिकारियों की मनमर्जी के चलते नियम विरुद्ध तरीके से सिगौंद स्थानांतरित किया जा रहा है। जबकि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिगौंद को सांदीपनि विद्यालय बनाकर किवलारी रैपुरा स्थानांतरित किया जा चुका है, अब सिगौंद में मांग के कारण वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल पनागर को सिगौंद भेजना क्या न्याय संगत है?

ज्ञातव्य हो कि वर्तमान समय में वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल पनागर की दर्ज संख्या कक्षा 6,7,8 की 450 है और कक्षा 9,10 की 200 के लगभग है। वहीं शासकीय वरिष्ठ बुनियादी शाला पनागर सन् 1810 से (210 बर्ष पुराना) संचालित एक प्राचीन विद्यालय है। शासन के शिक्षा विभाग के कर्ताधर्ता प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने के बजाय खुर्दबुर्द करने में लगे हैं। नगर में छात्रों की संख्या देखते हुए विद्यालय को अन्यत्र भेजना नगर हित एवं छात्र हित में नहीं है। उक्त आदेश के कारण नगर में आक्रोश व्याप्त है।

क्षेत्र के नरेन्द्र सेन, राजेन्द्र खरे, किशन विश्वकर्मा, अरविन्द पाठक, रमेश खम्परिया, आदि ने शासन से उक्त आदेश को निरस्त कर वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल पनागर को यथावत रखने की मांग की है अन्यथा की स्थिति में बृहद पैमाने पर आन्दोलन की चेतावनी भी दी है।

तारीख पर तारीख से किसान और आम जनता बेहाल

▸ 15 दिनों से कार्यालय है तहसीलदार विहीन

मझौली, नवभारत। तहसील कार्यालय मझौली में पिछले 15 दिनों से स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति न होने के कारण क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। आम जनता और किसान अपने जरूरी कामों के लिए भटकने को मजबूर हैं।

बताया जाता है कि शासन द्वारा जिस अधिकारी की यहां पदस्थापना की गई है, उन्हें एक साथ दो तहसीलों का प्रभार दे दिया गया है। दोहरी जिम्मेदारी के चलते अधिकारी किसी भी एक तहसील को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ही तहसीलों की जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है। पीड़ितों का कहना है कि तहसीलदार न होने से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, और जरूरी प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पूरी तरह लंबित पड़े हैं। सबसे बुरा हाल उन किसानों का है जो अपनी जमीनों से जुड़े मामलों को लेकर तहसील के चक्कर काट रहे हैं। राजस्व न्यायालयों में सुनवाई न होने के कारण आवेदकों को केवल अगली तारीखें थमाई जा रही हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। किसानों का कहना है कि खेती-किसानी के इस व्यस्त सीजन में हमें कलेक्ट्रेट और तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अधिकारी मिलते नहीं और हर बार नई तारीख दे दी जाती है। अगर यही स्थिति रही तो हमारे सारे काम अटक जाएंगे।'

कलेक्टर से पूर्णकालिक तहसीलदार की मांग

क्षेत्र के नागरिकों और किसान संगठनों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से गुहार लगाई है कि मझौली तहसील की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए तथा दोहरी जिम्मेदारी वाले प्रभार की व्यवस्था को खत्म कर तुरंत यहां एक पूर्णकालिक तहसीलदार की नियुक्ति की जाए।

डीएपी की जगह एनकेपी मिलने से किसान परेशान

उमरिया। प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद उपलब्ध कराने को लेकर एक बार फिर समस्याएं सामने आने लगी हैं। उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिल्हारी, कोटरी, अमरपुर, इंदवार, पनपथा सहित विभिन्न सेवा सहकारी समिति केंद्रों पर किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मांग के अनुरूप डीएपी (18:46:0) खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके स्थान पर एनपीके खाद दी जा रही है, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। साथ ही टोकन बुकिंग व्यवस्था और खाद की बढ़ती कीमतों को लेकर भी किसानों ने सवाल उठाए हैं।

विद्यार्थियों ने ली नशे से दूर रहने की शपथ

▸ नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 कार्यक्रम का आयोजित

सिहोरा, नवभारत। शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिहोरा -जबलपुर के एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थियों द्वारा आज 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन एनसीसी अधिकारी डॉ. वैशाली उइके के नेतृत्व में किया गया। रैली से पहले विद्यार्थियों ने हर प्रकार के नशे से दूर रहने की शपथ ली ।

'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान बताता है कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, करियर और समाज को भी प्रभावित करता है। युवाओं के लिए संदेश है कि वे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय को शिक्षा, खेल, योग, कला, नवाचार और राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाएँ। मित्रों के दबाव या जिज्ञासा में आकर किसी भी प्रकार के नशे की शुरुआत न करें। यदि कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा हो, तो उसे छिपाने के बजाय परिवार, शिक्षकों या विशेषज्ञों की सहायता लेकर इस आदत से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर विद्यार्थियों को नशे के प्रति जागरूकता लाने अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया है। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एस के मेहरोलिया रहे।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हुआ गंगापुर सिटी जंक्शन

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल का प्रमुख एवं व्यस्त गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप में विकसित होकर यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी निर्धारित कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आधुनिक वास्तुशिल्प, विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं और दिव्यांगजन-अनुकूल अधोसंरचना से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। साथ ही क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। पुनर्विकास कार्य के तहत लगभग 555 वर्गमीटर क्षेत्र में स्टेशन भवन का विस्तार और नवीनीकरण किया गया है। यात्रियों के लिए तीन नए वातानुकूलित प्रतीक्षालय, चार आधुनिक शौचालय ब्लॉक, लगभग 10 हजार वर्गमीटर का सर्कुलेटिंग एरिया तथा बेहतर यातायात व्यवस्था विकसित की गई है। विभिन्न प्लेटफॉर्मों को जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ा आधुनिक फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है स्टेशन

इसके अलावा नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सरफेसिंग, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अन्य यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। स्टेशन को पूर्णत: दिव्यांगजन-अनुकूल बनाया गया है। यहां रैंप, टैक्टाइल पाथ, दिव्यांग-अनुकूल शौचालय, पेयजल सुविधा, व्हीलचेयर, हेल्प बूथ, पृथक पार्किंग और सुगम पहुंच मार्ग विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही आधुनिक साइनेज, ट्रेन सूचना बोर्ड, कोच पोजीशन डिस्प्ले सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म घड़ियां भी स्थापित की गई हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार पुनर्विकसित गंगापुर सिटी जंक्शन यात्रियों को आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा देगा।

चित्रकला प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने लिया भाग

जबलपुर, नवभारत। प्रधानमंत्री द्वारा 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 अमृत भारत स्टेशनों के लोकार्पण से पूर्व पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे के छह पुनर्विकसित स्टेशनों जबलपुर मंडल के ब्योहारी, भोपाल मंडल के शिवपुरी, अशोकनगर, साँची एवं विदिशा तथा कोटा मंडल के गंगापुर सिटी जंक्शन पर विद्यालय स्तरीय चित्रकला, निबंध एवं कविता लेखन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय रेल के आधुनिकीकरण, स्टेशन पुनर्विकास, स्वच्छता, विरासत संरक्षण और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना था। इन प्रतियोगिताओं में शासकीय एवं निजी विद्यालयों के 2,000 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जबकि विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 100 से अधिक विद्यार्थियों का चयन विजेता के रूप में किया गया।

विविध प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन

ब्योहारी में चित्रकला, निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जबकि शिवपुरी, अशोकनगर, साँची और विदिशा में चित्रकला, निबंध, कविता लेखन के साथ देशभक्ति एवं लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को आकर्षक बनाया। गंगापुर सिटी जंक्शन पर विद्यार्थियों ने 'मेरे शहर का विकसित स्टेशन कैसा हो' और 'विकसित भारत के निर्माण में मेरा योगदान' जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी सृजनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिला, वहीं उन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना और भारतीय रेल के विकास कार्यों की भी जानकारी प्राप्त हुई। रेलवे का मानना है कि इस प्रकार के आयोजन नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ने, रेलवे के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सवाल | सीवर परियोजना पर उठे सवाल : अब जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री से मांगी उच्चस्तरीय जांच

पांच दिन पहले ही मिला था उत्कृष्ट कार्य का प्रशस्ति पत्र

डिंडौरी, नवभारत। नगर परिषद डिंडौरी में करोड़ों रुपये की लागत से संचालित सीवरेज परियोजना को लेकर विरोधाभासी तस्वीर सामने आई है। एक ओर 10 जुलाई को जिला प्रशासन ने परियोजना के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की सराहना करते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा कार्यदायी संस्था को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया था, वहीं महज पांच दिन बाद नगर परिषद के अध्यक्ष - उपाध्यक्ष सहित चार जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी को ज्ञापन सौंपकर परियोजना में गंभीर तकनीकी अनियमितताओं, गुणवत्ताहीन निर्माण और वित्तीय गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है।

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सीवर लाइन निर्माण में स्वीकृत डीपीआर एवं तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पाइपों की जॉइंटिंग भी मानकों के विपरीत किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने का खतरा बढ़ सकता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि खुदाई के बाद सड़कों का समुचित रेस्टोरेशन नहीं किया जा रहा है। जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है।

पांच दिन में बदली तस्वीर

गौरतलब है कि 10 जुलाई को जारी समाचार में जिला प्रशासन ने एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी माध्यम से संचालित सीवरेज परियोजना को डिंडौरी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया था। प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया था कि परियोजना के तहत शहर के आठ प्रमुख नालों को इंटरसेप्ट कर उनका गंदा पानी नर्मदा में जाने से रोका गया है, जिससे नर्मदा संरक्षण, शहरी स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूती मिली है। कलेक्टर ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों, अभियंताओं और कार्यदायी संस्था की सराहना भी की थी। इधर, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अशोक सारस, उपाध्यक्ष सारिका मनीष नायक, पार्षद रितेश जैन, रजनीश राय और स्मिता अजय बर्मन ने प्रभारी मंत्री को दिए ज्ञापन में मांग की है कि करोड़ों रुपये की इस परियोजना की किसी स्वतंत्र एवं सक्षम तकनीकी एजेंसी से तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही निर्माण एजेंसी से सभी त्रुटिपूर्ण कार्य अपने स्वयं के व्यय पर दोबारा कराने के निर्देश दिए जाएं।

उठ रहे हैं कई सवाल

जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में परियोजना को उत्कृष्ट बताते हुए प्रशस्ति पत्र दिए जाने और उसके कुछ ही दिनों बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीर तकनीकी खामियों एवं गुणवत्ताहीन निर्माण के आरोप लगाए जाने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रभारी मंत्री इस मामले में क्या निर्णय लेती हैं और क्या परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाएगी।